

एम/एस. इंडिया मीटर्स लि.

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(सिविल अपील संख्या 1032-1033, 2003)

सितम्बर 7, 2010

(दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा, जे.जे.)

बिक्री कर-डीलर द्वारा किया गया मालभाड़ा और बीमा शुल्क-बिक्री कर लगाना - माना गया: डीलर द्वारा वहन किया गया मालभाड़ा और सी बीमा शुल्क बिक्री मूल्य का हिस्सा है - इसलिए, यह 'टर्नओवर' और बिक्री के दायरे में आएगा इस पर टैक्स लगता है - तमिलनाडु जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1959- एस.एस. 2(एन) और (आर) - तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर नियम, 1959-आर। 6 (सी) - केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956।

शब्द और वाक्यांश - 'बिक्री और 'टर्नओवर' - एसएस के संदर्भ में अर्थ। तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के क्रमशः 2(एन) और (आर)।

अपीलकर्ता-निर्धारिती ने अपने कर योग्य टर्नओवर में माल दुलाई शुल्क को शामिल नहीं किया। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि

निर्धारिती ने डेबिट नोटों के तहत माल ढुलाई शुल्क और बीमा शुल्क अलग-अलग एकत्र किया था, लेकिन इसे मासिक रिटर्न में नहीं दिखाया गया था। निर्धारण प्राधिकारी ने उस राशि का 50% मूल्यांकन किया, माल ढुलाई शुल्क के रूप में, और निर्धारिती द्वारा बिक्री मूल्य का हिस्सा बनने वाले माल ढुलाई की उस राशि पर कर लगाया गया। आदेश के विरुद्ध निर्धारिती की अपील सफल हुई। राजस्व द्वारा आगे की अपील को तमिलनाडु विशेष कराधान न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी। निर्धारिती ने विशेष न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ रिट जी याचिका दायर की। इसलिए कोर्ट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। तत्काल अपीलें दायर की गईं।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया गया।

1. डीलर द्वारा वहन किया गया माल भाड़ा और बीमा शुल्क बिक्री मूल्य का हिस्सा होता है। तत्काल मामले में, पार्टियों द्वारा और उनके बीच विशिष्ट अनुबंध किया गया था और अनुबंध के प्रासंगिक खंड के अनुसार, माल का स्वामित्व आपूर्तिकर्ता के पास तब तक रहेगा जब तक कि उन्हें गंतव्य स्टेशन पर वितरित नहीं किया जाता। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करना उचित था। (पैरा 41, 42 और 43,)(37-ई-जी)

2. वर्तमान मामले में, भाड़े का भुगतान करने का दायित्व स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता पर था क्योंकि कोई बिक्री नहीं हुई थी, जब तक कि सामान खरीदार के परिसर में वितरित नहीं किया गया था और ऐसा वितरित करने के लिए, निर्धारिती को आवश्यक रूप से खर्च करना पड़ता था भाड़ा प्रभार।
(पैरा 14) (29-बी)

3. यह सच है कि तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर नियम, 1959 का नियम 6(सी) कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय माल दुलाई पर लागत में कटौती की अनुमति देता है। हालाँकि, उस प्रावधान को "टर्नओवर" की परिभाषा के साथ-साथ तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (आर) और 2 (एन) में क्रमशः "बिक्री की परिभाषा के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। एक निर्धारिती/डीलर के टर्नओवर में वह कुल राशि शामिल होगी जिसके लिए सामान खरीदा या बेचा जाता है। इसलिए, यह वह राशि है जिसके लिए सामान खरीदा या बेचा जाता है, जो टर्नओवर का हिस्सा बनता है, और किसी चीज को बेचा जाना तभी कहा जा सकता है जब लेनदेन "बिक्री की परिभाषा के दायरे में आता है। जब संपत्ति या माल का हस्तांतरण खरीदार के स्थान पर होना है, जहां विक्रेता माल परिवहन करने के लिए बाध्य है, तो विक्रेता द्वारा अपने निर्माण के स्थान से माल ले जाने के लिए माल दुलाई पर ये व्यय किए जाते हैं। जिस स्थान पर उसे अनुबंध के तहत वितरित करना आवश्यक है, इस प्रकार वह उस राशि का हिस्सा बन जाएगा जिसके लिए विक्रेता द्वारा

खरीदार को सामान बेचा जाता है और "टर्नओवर" के दायरे में आएगा।
(पैरा 18 और 20) (30-सी-डी; जी-एच; 31-ए)

डायर मीकिन बेवअरीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1970) 3
एससीसी 253; हिंदुस्तान शुगर मिल्स बनाम केरल राज्य। राजस्थान
और अन्य (1978) 4 एससीसी 271; सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया
लिमिटेड बनाम सहायक बिक्री कर आयुक्त, इंदौर और अन्य (1980) 1
एससीसी 71; सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम
वाणिज्यिक कर आयुक्त एसपी कर्नाटका 1980 (सप्प) एससीसी 373;
टीवीएल रैमको सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (पी) लिमिटेड आदि: आदि और
तमिलनाडु राज्य आदि। (1993) 1 एससीसी192; (बिहार राज्य विद्युत
बोर्ड और अन्य वी. उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज और अन्य। (1997) 5
एससीसी 289; ब्लैक डायमंड बेवरेजेज और अन्य। वी. वाणिज्यिक कर
अधिकारी, केंद्रीय अनुभाग, मूल्यांकन विंग, "कलकत्ता और अन्य (1998) 1
एससीसी 458, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली बनाम मारुति उद्योग
लिमिटेड (2002) 3 एससीसी 547; ए.पी. राज्य ए.पी. पेपर मिल्स
लिमिटेड (2005) 1 एससीसी 719 पर भरोसा है।

हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
(1969) 24 एसटीसी 487 (1969) 1 एससीडब्ल्यूआर 560; ईआईडी पैरी

(1) लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त और अन्य (2000) 2
एससीसी 321, संदर्भित

पैपरिका लिमिटेड और अन्य। वी. व्यापार मंडल (1944) सभी
ई:आर। 372; लव बनाम नॉर्मन राइट (बिल्डर्स) लिमिटेड (1944) 1
सभी ई.आर. 618, संदर्भित।

कानून

(1969) 24 एसटीसी 487	संदर्भित	पैरा 13
(2000) 2 एससीसी 321	संदर्भित	पैरा, 17
(1944) सभी ई.आर. 372	संदर्भित	पैरा 23
(1944) 1 सभी ई.आर.618	संदर्भित	पैरा 24
(1970) 3 एससीसी 253	संदर्भित	पैरा 25
(1978) 4 एससीसी 271	संदर्भित	पैरा-31
(1980) 1 एससीसी 71	संदर्भित	पैरा 34
1980, (सप्प) एससीसी 373	संदर्भित	पैरा 35
(1993) 1 एससीसी 192	संदर्भित	पैरा 36
(1997) (5 एससीसी 289)	संदर्भित	पैरा 37

(1998) 1 एससीसी 458	संदर्भित	पैरा 38
(2002) 3 एससीसी 547	संदर्भित	पैरा 39
(2005) 1 एससीसी 719	संदर्भित	पैरा 40

सिविल अपील की संख्या 1032-1033।

मद्रास उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. संख्या 21298 और 1993 के टीसी संख्या 980 में पारित 2001 के निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2001 से।

के.के. मणि, अंकित स्वरूप, मयूर आर. शाह अपीलकर्ता के लिए।

नेदुमारन, विमल दुबे प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

1. ये अपीलें 2001 की रिट याचिका संख्या 21298 और कर मामले संख्या 980 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2001 के खिलाफ निर्देशित हैं।

2. अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है। अपीलकर्ता बिजली के मीटर बनाता है और बिजली बोर्डों को इसकी आपूर्ति करता है। अपीलकर्ता तमिलनाडु सामान्य बिक्री, कर

अधिनियम, 1959 के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक डीलर भी है।

3. इन अपीलों के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार दोहराए गए हैं उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, ग्रुप viii एक मूल्यांकन अधिकारी, प्रवर्तन दक्षिण ने 30.6.1989 को तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम (इसके बाद टीएनजीएसटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (इसके बाद सीएसटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत दो अलग-अलग आदेश पारित किए। माल दुलाई और बीमा शुल्क पर कर लगाया जाना था और बी को टर्नओवर में शामिल किया जाना था और इस प्रकार 7,97,864/- रुपये की

राशिको कर योग्य में शामिल करने की मांग की गई थी। टीएनजीएसटी अधिनियम के तहत आकलन वर्ष 1986-87 के लिए टर्नओवर पर 10 प्रतिशत कर योग्य है और सीएसटी अधिनियम के तहत इसी अवधि से संबंधित राशि 8,48,265/- रुपये है।

4. अपीलकर्ता ने अपीलीय सहायक आयुक्त (सीटी), कांचीपुरम, तमिलनाडु के समक्ष टीएनजीएसटी अधिनियम के साथ-साथ सीएसटी अधिनियम के तहत अपील की। अपीलीय सहायक आयुक्त ने मूल्यांकन के नए आदेश पारित करने के लिए मामलों को अपीलीय सहायक आयुक्त को भेज दिया।

5. अपीलकर्ता ने दो अपीलें दायर की थीं तमिलनाडु बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अतिरिक्त पीठ), मद्रास और अपीलें टी.ए. के रूप में पंजीकृत की गईं। 1991 की संख्या 766 और 1991 का 767. उक्त न्यायाधिकरण द्वारा दोनों अपीलें स्वीकार की गईं।

6. उक्त अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें 1993 के कर मामले संख्या 979 और 1993 के 980 के रूप में पंजीकृत किया गया था। तमिलनाडु कराधान विशेष न्यायाधिकरण के गठन के परिणामस्वरूप, टीएनजीएसटी अधिनियम के तहत, पुनरीक्षण याचिकाओं को उक्त न्यायाधिकरण को भेजा गया था।

7. तमिलनाडु कराधान विशेष न्यायाधिकरण, चेन्नई ने 19 सितंबर, 2000 के आदेश द्वारा माना कि माल दुलाई शुल्क जी बिक्री मूल्य का हिस्सा बनता है और वास्तविक माल दुलाई शुल्क निकालने के लिए मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दिया गया था। नतीजतन, अपीलीय सहायक आयुक्त (सीटी), कांचीपुरम के आदेश को बहाल कर दिया गया और परिणामस्वरूप प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

8. अपीलकर्ता ने तमिलनाडु कराधान विशेष न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उच्च

न्यायालय में यह आग्रह किया गया था कि भुगतान से संबंधित अनुबंध के खंड में प्रावधान है कि "पूर्ण उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के साथ प्रत्येक खेप के 100 प्रतिशत मूल्य का भुगतान प्राप्ति के तुरंत बाद केंद्रीय भुगतान, मद्रास में किया जाएगा।" खरीद आदेश शर्तों के अधीन, संबंधित सिस्टम के मुख्य स्टोर कीपर से डिलीवरी चालान की पावती की प्रमाणित प्रतियां।

9. अनुबंध में दिए गए खंड के अनुसार माल के स्वामित्व का हस्तांतरण केवल ग्राहक के स्थान पर माल की डिलीवरी पर ही होना था और ग्राहक का भुगतान करने का दायित्व डिलीवरी के प्रभावित होने के बाद ही उत्पन्न होगा। अनुबंध में कीमत से संबंधित खंड में यह भी प्रावधान किया गया था कि यह प्रति यूनिट पूर्व-फैक्टरी डिलीवरी के लिए देय था। इसमें ऐसे पूर्व-कारखाना मूल्य के अलावा, उत्पाद शुल्क और वैधानिक लेवी के भुगतान का प्रावधान किया गया था, साथ ही यह तथ्य भी था कि उल्लिखित पूर्व-कारखाना मूल्य में बिक्री कर शामिल नहीं था।

10. खंड 3 (बी) में बिक्री कर से संबंधित खंड में आगे यह प्रावधान किया गया है कि"

उचित बिक्री कर, यदि कोई हो, का भुगतान माल की कीमत से अधिक किया जाएगा।" इस क्रम में स्वीकार किया गया। खंड में यह भी प्रावधान है कि बिक्री कर और उत्पाद शुल्क केवल पूर्व-कारखाना मूल्य पर देय होगा।

11. अपीलकर्ता ने शुरू में अपने कर योग्य टर्नओवर में माल ढुलाई शुल्क को शामिल नहीं किया था। मूल मूल्यांकन वर्ष 1986-87 के लिए माल ढुलाई शुल्क को ध्यान में रखे बिना किया गया था। 27.2.1987 को एक निरीक्षण हुआ था जिसमें निरीक्षण अधिकारी ने पाया था कि निर्धारिती ने डेबिट नोटों के तहत कुल 16,96,530/-रुपये की माल ढुलाई शुल्क और बीमा शुल्क अलग-अलग एकत्र किया था, लेकिन इसे इसमें नहीं दिखाया गया था। मासिक रिटर्न. मूल्यांकन प्राधिकारी. इसलिए, बीमा राशि के लिए भत्ता बनाने के बाद, माल ढुलाई शुल्क के रूप में 16,96,530/- रुपये की राशि का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया और लगाए गए माल ढुलाई की उस राशि पर कर लगाया गया।

बिक्री मूल्य का हिस्सा बनने वाले निर्धारिती द्वारा उस आदेश के खिलाफ निर्धारिती की अपील सफल होने के बाद, राजस्व द्वारा एक और अपील की गई, जिसे तमिलनाडु विशेष कराधान न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई। करदाता अब हमारे सामने ट्रिब्यूनल के उस आदेश की सत्यता पर सवाल उठा रहा है।

12. अपीलकर्ता का दावा है कि चूंकि अनुबंध में पूर्व-कारखाना मूल्य और बीमा और माल ढुलाई शुल्क को अलग किया गया है, और, तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर नियमों के नियम 6 (सी) के तहत, भाड़ा जब, निर्दिष्ट और डीलर द्वारा शुल्क लिया जाता है अलग से, डीलर की कीमत में इसे

शामिल किए बिना, यहां लगाए गए भाड़े को बिक्री मूल्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता था और कर के अधीन नहीं किया जा सकता था।

13. अपीलकर्ता के वकील ने हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में इस कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। (1969) 24 एसटीसी 487 (1969) 1 एससीडब्ल्यूआर 560, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए उस निर्णय में, यह माना गया कि निर्धारिती को कीमत के रूप में केवल कैटलॉग की कीमत से कम राशि प्राप्त हुई थी। माल दुलाई शुल्क, जो खरीदार ने भुगतान किया था और इसलिए जो कर योग्य था वह केवल वास्तव में प्राप्त कीमत थी। यह निर्णय पाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में दिया गया था, जिससे पता चला कि निर्धारिती ने स्टॉकिस्ट को "डिलीवरी की तारीख" की शर्त के साथ माल भेजा था, का मतलब रेलवे रसीद की तारीख होगा। न्यायालय ने पाया कि खरीदार/स्टॉकिस्ट की ओर से माल दुलाई शुल्क का भुगतान करने के समझौते पर और ऐसे माल शुल्क को कैटलॉग मूल्य से काट लिया गया था, माल दुलाई शुल्क बेची गई वस्तुओं की कीमत का हिस्सा नहीं था। इस फैसले को हिंदुस्तान शुगर मिल्स बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1978) 4 एससीसी 271 के मामले में इस न्यायालय की बाद की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा समझाया गया था। इस न्यायालय ने फैसले के बाद के भाग में मामले में

निम्नलिखित कथन निकाला हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा)।

हमारे निर्णय में, अनुबंध की शर्तों के तहत, कंपनी पर माल ढुलाई का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है, और अनुबंध की शर्तों के तहत माल की बिक्री के लिए प्राप्त मूल्य, माल की बिक्री के लिए चालान राशि और भाड़ा कम है।

14. इस मामले में, माल ढुलाई का भुगतान करने का दायित्व स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता पर था, क्योंकि कोई बिक्री नहीं हुई थी, जब तक कि सामान खरीदार के परिसर में वितरित नहीं किया गया था और इस तरह वितरित करने के लिए, निर्धारिती को आवश्यक रूप से माल ढुलाई शुल्क वहन करना पड़ता था।

15. समझौते के खंड 6 के साथ पढ़े गए खंड 10 में दिए गए अनुसार माल के स्वामित्व का हस्तांतरण खरीदार के परिसर में डिलीवरी के स्थान पर होना था। यद्यपि अनुबंध में विद्युत मीटरों की कीमत का उल्लेख फैक्टरी-पूर्व कीमत के रूप में किया गया था, लेकिन डिलीवरी फैक्टरी के गेट पर नहीं की गई थी। इसलिए, फैक्टरी गेट पर कीमत क्या होगी, इसका विवरण उस अवधि के संदर्भ में नहीं है जिसके अधीन बिक्री पर सहमति व्यक्त की गई थी, यह उस बिंदु या स्थान को प्रस्तुत करता है जिस पर बिक्री के बारे में कहा जा सकता है पूरा हो गया यदि बिक्री

कारखाने के गेट पर पूरी हो गई होती, तो उसके बाद माल ढुलाई शुल्क के माध्यम से किए गए खर्च को 'व्यय के रूप में माना जाता जो बिक्री के बाद के व्यय की प्रकृति में था और, यदि विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है, खरीदार की ओर से ऐसे विक्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि के रूप में माना जाता है।

16. उपरोक्त दोनों मामले इस तथ्य पर जोर देते हैं कि विक्रेता द्वारा माल ढुलाई पर किया गया खर्च बिक्री मूल्य का हिस्सा होगा, जब तक कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो जाता, जो कि एकमात्र है जिस तरह से बिक्री संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29 ए की शुरुआत से पहले हो सकती थी।

17. विद्वान वकील ने ईआईडी पैरी (1) लिमिटेड, बनाम वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त और अन्य (2000) 2 के मामले में, इस न्यायालय के फैसले पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। एससीसी 321, उसमें जिस प्रश्न पर विचार किया गया वह चीनी द्वारा दी जाने वाली परिवहन सब्सिडी को शामिल करने का था।

गन्ना उत्पादकों के लिए एक निर्माता, जिसे अनुबंध की शर्तों के तहत कारखाने में गन्ने की आपूर्ति करना आवश्यक था। इस प्रकार दी गई सब्सिडी को न्यायालय ने कीमत का हिस्सा माना क्योंकि वह राशि निर्माता द्वारा, निस्संदेह, उत्पादक/विक्रेता से माल की आपूर्ति सुनिश्चित

करने के लिए दी गई थी। उस मामले में न्यायालय ने तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 6(सी) पर विचार नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं था।

18. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमों का नियम 6 (सी) कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय माल ढुलाई पर लागत में कटौती की अनुमति देता है। हालाँकि, उस प्रावधान को "टर्नओवर" की परिभाषा के साथ-साथ अधिनियम की धारा 2(आर) और 2(एन) में क्रमशः "बिक्री की परिभाषा के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम में "टर्नओवर" को अन्य बातों के साथ-साथ परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "कुल राशि जिसके लिए सामान खरीदा या बेचा जाता है या वितरित किया जाता है या आपूर्ति की जाती है या अन्यथा खंड (एन) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से निपटाया जाता है"।

19. "बिक्री को अन्य बातों के साथ-साथ धारा 2(एन) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल के रूप में संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण (बंधक, दृष्टिबंधक, शुल्क या प्रतिज्ञा के अलावा) नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए व्यवसाय का क्रम"। यह परिभाषा "बिक्री की परिभाषा के अंतर्गत कई अन्य लेनदेन को भी शामिल करती है। एक निर्धारित धीलर के टर्नओवर में एफ कुल राशि शामिल होगी जिसके लिए सामान खरीदा या बेचा

जाता है। इसलिए, यह वह राशि है जिसके लिए सामान खरीदा या बेचा जाता है, जो टर्नओवर का हिस्सा बनता है, और किसी चीज को बेचा जाना तभी कहा जा सकता है जब लेनदेन "बिक्री" की परिभाषा के दायरे में आता है।

20. जब संपत्ति या माल का हस्तांतरण खरीदार के स्थान पर होना है, जहां विक्रेता माल परिवहन करने के लिए बाध्य है, तो माल को अपने स्थान से ले जाने के लिए विक्रेता द्वारा माल ढुलाई पर किया गया व्यय उस स्थान पर निर्माण करना जहां उसे एच अनुबंध के तहत वितरित करना आवश्यक है, इस प्रकार राशि का हिस्सा बन जाएगा जो सामान विक्रेता द्वारा खरीदार को बेचा जाता है और "टर्नओवर" के दायरे में आएगा।

21. तमिलनाडु राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि माल की बिक्री मूल्य में माल ढुलाई और बीमा शुल्क शामिल हैं। भले ही माल ढुलाई और बीमा शुल्क बिल में अलग-अलग दिखाया गया हो और माल की कीमत में जोड़ा गया हो, भुगतान का चरित्र वही रहेगा। चूंकि माल ढुलाई और बीमा शुल्क डीलर द्वारा बिक्री के स्थान पर खरीदार को सामान उपलब्ध कराने में किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे डीलर को माल की लागत में अतिरिक्त जोड़ देंगे और स्पष्ट रूप से कीमत का एक घटक होंगे। क्रेता. माल ढुलाई और बीमा शुल्क की राशि क्रेता द्वारा किसी वैधानिक या अन्य दायित्व के तहत नहीं बल्कि माल की बिक्री के

लिए प्रतिफल के हिस्से के रूप में देय होगी और इसलिए, बिक्री मूल्य का हिस्सा होगी।

22. कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हम महत्वपूर्ण अंग्रेजी और भारतीय मामलों का उल्लेख करना चाहेंगे।

अंग्रेजी मामले:

23. पैपरिका लिमिटेड और अन्य बनाम व्यापार मंडल (1944) सभी ई.आर. 372 में, अदालत ने निम्नानुसार कहा:

“जब भी किसी बिक्री पर खरीद कर लगता है, तो वह कर संभवतः उस कीमत को प्रभावित करता है जिस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी विक्रेता मांग करता है, लेकिन यह वह कीमत नहीं रह जाती है जिसे खरीदार को भुगतान करना पड़ता है, यहां तक कि कीमत को 'एक्स प्लस' के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। खरीद कर।”

24. इस मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने लव बनाम नॉर्मन राइट (बिल्डर्स) लिमिटेड (1944) 1 ऑल ई.आर. 618- में गोडार्ड, एल.जे. द्वारा कही गई बातों को भी अनुमोदन के साथ उद्धृत किया।

“जहां किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है, चाहे वह खरीद कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क हो, कर उस कीमत का हिस्सा बन जाता है जिसे आम तौर पर खरीदार को भुगतान

करना होगा। कीमत तम्बाकू के एक औंस का मूल्य कर की दर के कारण होता है, लेकिन बिक्री पर केवल एक ही विचार किया जाता है, हालांकि यह लागत प्लस लाभ प्लस टैक्स से बना होता है। इसलिए यदि कोई विक्रेता बिक्री के लिए सामान पेश करता है, तो उसे एक कीमत उद्धृत करनी होगी जिसमें कर भी शामिल है यदि वह इसे खरीदार को देना चाहता है। यदि खरीदार कीमत से सहमत है, तो उसे इस बात पर विचार नहीं करना है कि यह कैसे बनी है या विक्रेता ने कर शामिल किया है या नहीं।”

और स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया:

“जहां तक क्रेता का सवाल है, वह सामान के लिए वही भुगतान करता है जो विक्रेता मांगता है, अर्थात् कीमत, भले ही इसमें कर शामिल हो। यह बिक्री के लिए संपूर्ण विचार है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरी राशि का भुगतान क्यों किया जाए क्रेता द्वारा विक्रेता को बिक्री के प्रतिफल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और टर्नओवर में शामिल किया जाना चाहिए”

भारतीय मामले:

25. डायर मीकिन ब्रिवअरीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1970) 3 एससीसी 253 में, मुख्य न्यायाधीश, शाह (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने अदालत के लिए बोलते हुए कहा कि माल दुलाई और पैकिंग और डिलीवरी शुल्क के लिए किए गए व्यय से पहले नियम 9 (एफ) के तहत बिक्री और कारखानों से कंपनी के गोदाम तक माल परिवहन स्वीकार्य नहीं है। केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1963।

26. इस मामले के तथ्यों के अनुसार, डायर मीकिन ब्रिवअरीज लिमिटेड केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत "भारत में निर्मित विदेशी शराब" के डीलर के रूप में पंजीकृत है। कंपनी का व्यवसाय स्थान एर्नाकुलम, केरल में है। कंपनी द्वारा बेची जाने वाली शराब का निर्माण या उत्पादन यूपी राज्य के विभिन्न स्थानों पर डिस्टिलरी या ब्रिवअरीज में किया जाता है। और हरियाणा. कंपनी द्वारा अपनी ब्रिवअरीज और डिस्टिलरीज से एर्नाकुलम में अपने व्यवसाय के स्थान पर बिक्री के लिए शराब पहुंचाई जाती है। बेची गई शराब के प्रत्येक ब्रांड के संबंध में एक समान "एक्स-फैक्टरी कीमत" बनाए रखना कंपनी की प्रथा है। माल दुलाई और अन्य शुल्कों के लिए उचित राशि को पूर्व-कारखाना मूल्य में जोड़ने के बाद विभिन्न केंद्रों पर।

27. 1963-64 के लिए बिक्री कर के आकलन की कार्यवाही में कंपनी ने केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1963 के नियम 9 (एफ) के तहत

“माल ढुलाई और हैंडलिंग शुल्क के संबंध में स्वीकार्य कटौती के रूप में 59,188.99 रुपये का दावा किया। कर योग्य टर्नओवर की गणना में, ग्राहकों से एकत्र किया गया। बिक्री कर अधिकारी ने दावे को खारिज कर दिया, और अपीलीय सहायक आयुक्त और बिक्री कर न्यायाधिकरण द्वारा आदेश की पुष्टि की गई। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। कंपनी ने विशेष अनुमति के साथ इस न्यायालय में अपील की है।

28. केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1963 का नियम 9 (एफ) प्रदान करता है:

“कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करने में, निम्नलिखित खंडों में निर्दिष्ट राशि, उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, डीलर के कुल टर्नओवर से काट ली जाएगी....

xxx

(एफ) निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत आने वाली सभी राशियाँ, जब डीलर द्वारा अलग से निर्दिष्ट और चार्ज की जाती हैं, उन्हें बेची गई वस्तुओं की कीमत में शामिल किए बिना,

(i) माल ढुलाई,

(ii) पैकिंग और डिलीवरी के लिए शुल्क।”

29. कंपनी का दावा है कि माल दुलाई के लिए और कारखानों से एर्नाकुलम में गोदाम तक माल के "हैंडलिंग शुल्क के लिए खर्च की गई राशि कर योग्य टर्नओवर से बाहर करने के लिए उत्तरदायी है और कर अधिकारियों और उच्च न्यायालय ने गलती की थी। कटौती की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

30. इस अदालत ने केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1963 के नियम 9 (एफ) की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य डीलर द्वारा किए गए मूल्य, व्यय के किसी भी घटक को कर योग्य टर्नओवर से बाहर करना नहीं है, जो उसे पहले करना पड़ता था। बिक्री करना और इच्छुक ग्राहक बी को बिक्री के स्थान पर सामान उपलब्ध कराना।

31. इस अदालत के पास हिंदुस्तान शुगर मिल्स (सुप्रा) के मामले में समान मुद्दों से निपटने का अवसर था। पी.एन. भगवती, जे. (जैसा कि उनका आधिपत्य तब था) ने स्पष्ट रूप से माना कि नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के कारण, जो हमारे समक्ष दोनों अपीलों में खरीददारों के साथ निर्धारिती द्वारा किए गए सीमेंट की बिक्री के लेनदेन को नियंत्रित करते थे, राशि माल दुलाई का हिस्सा 'बिक्री मूल्य का हिस्सा बनता है।

32. इस फैसले में, अदालत ने फैसले के पैरा 8 में एक उदाहरण देकर कानून के संपूर्ण सिद्धांत को व्यापक रूप से समझाया, जो इस प्रकार है: -

“8. उदाहरण के लिए, एक डीलर द्वारा देय उत्पाद शुल्क लें जो एक निर्माता है। जब वह अपने द्वारा निर्मित माल बेचता है, तो वह हमेशा उत्पाद शुल्क को क्रेता को दे देता है। आमतौर पर इसे बिल में एक अलग आइटम के रूप में नहीं दिखाया जाता है। लेकिन यह उसके द्वारा ली गई कीमत में शामिल है। ऐसे मामले में 'बिक्री मूल्य उत्पाद शुल्क सहित पूरी कीमत हो सकती है क्योंकि वह माल की बिक्री के लिए क्रेता द्वारा देय प्रतिफल होगा। सच है, उत्पाद शुल्क मूल्य का शुल्क घटक डीलर के खजाने में अतिरिक्त नहीं होगा, क्योंकि यह उसे माल के निर्माण पर पहले से ही भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिपूर्ति करेगा। लेकिन फिर भी, यह इसका हिस्सा होगा 'बिक्री मूल्य' क्योंकि यह क्रेता द्वारा डीलर को देय प्रतिफल का एक घटक है। यह केवल माल की बिक्री के लिए प्रतिफल के भाग के रूप में है कि उत्पाद शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि क्रेता द्वारा देय होगी। वहाँ है दायित्व का कोई अन्य तरीका, वैधानिक या अन्यथा, जिसके तहत खरीद पर डीलर को उत्पाद शुल्क की राशि का भुगतान करना होगा।

और, इस तर्क पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उत्पाद शुल्क की राशि डीलर द्वारा ली गई कीमत में शामिल

है या बिल में एक अलग आइटम के रूप में दिखाई गई है। किसी भी स्थिति में, यह 'बिक्री मूल्य का हिस्सा होगा। इसी तरह, किसी डीलर द्वारा देय बिक्री कर की राशि, चाहे वह कीमत में शामिल हो या एक अलग वस्तु के रूप में जोड़ी गई हो, जैसा कि आमतौर पर होता है, 'बिक्री मूल्य का हिस्सा बनती है। यह सामान की बिक्री के प्रतिफल के हिस्से के रूप में क्रेता द्वारा डीलर को देय है और इसलिए परिभाषा के पहले भाग में आता है।”

33. इस न्यायालय द्वारा अन्य मामलों में बाद के कई निर्णयों में इस निर्णय का पालन किया गया है।

34. सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सहायक बिक्री कर आयुक्त, इंदौर और अन्य (1980) 1 एससीसी 71 में इसी तरह का प्रश्न विचार के लिए उठा। इस मामले में, जबकि हिंदुस्तान शुगर मिल्स (सुप्रा) के मामले के बाद यह अदालत स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 2 (पी) में निहित शब्द की परिभाषा के पहले भाग के अर्थ के भीतर माल दुलाई की राशि बिक्री मूल्य का हिस्सा बनती है। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954.

35. सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, कर्नाटक 1980 (अनुपूरक) एससीसी 373 इस अदालत ने निम्नानुसार देखा:

“यह प्रश्न अब एकीकृत नहीं है और यह इस न्यायालय द्वारा हिंदुस्तान शुगर मिल्स बनाम राजस्थान राज्य (1978)

4 एससीसी 271 में दिए गए एक हालिया फैसले से समाप्त हुआ है। उस मामले में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सीमेंट नियंत्रण आदेश के प्रावधान, जो निर्धारिती द्वारा क्रेताओं के साथ किए गए सीमेंट की बिक्री के लेन-देन को नियंत्रित करते हैं, माल दुलाई की राशि उस शब्द की परिभाषा के पहले भाग के अर्थ के भीतर “बिक्री मूल्य का हिस्सा बनती है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) और निर्धारिती के कारोबार में शामिल थी। यह निर्णय पूरी तरह से वर्तमान मामले को कवर करता है और इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि उच्च न्यायालय का यह विचार सही था कि माल दुलाई की राशि बिक्री मूल्य का हिस्सा थी और इसे अपीलकर्ता के कर योग्य कारोबार में शामिल किया गया था”

36. टीवीएल रैमको सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (पी) लिमिटेड आदि आदि बनाम तमिलनाडु राज्य आदि में (1993) 1 एससीसी 192 इस अदालत ने हिंदुस्तान शुगर मिल्स (सुप्रा) के मामले में अनुपात का पालन करते हुए) निम्नानुसार मनाया गया:

“(I) केंद्रीय बिक्री कर और तमिलनाडु बिक्री कर के प्रयोजनों के लिए कर योग्य टर्नओवर पर पहुंचने में माल दुलाई शुल्क शामिल किया जाना चाहिए और

(II) पैकिंग शुल्क और उस पर उत्पाद शुल्क होना चाहिए। करयोग्य टर्नओवर की गणना में इसे भी शामिल किया जाएगा

केंद्रीय बिक्री कर और तमिलनाडु बिक्री दोनों के उद्देश्य कर।”

37. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज और अन्य (1997) 5 एससीसी 289 में इस अदालत ने हिंदुस्तान ई शुगर मिल्स (सुप्रा) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया और कानूनी स्थिति दोहराई कि बिक्री मूल्य होगा उत्पाद शुल्क सहित संपूर्ण कीमत होगी क्योंकि वह माल की बिक्री के लिए क्रेता द्वारा देय प्रतिफल होगा।

38. ब्लैक डायमंड बेवरेजेज और अन्य के मामले में। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, केंद्रीय अनुभाग, मूल्यांकन विंग, कलकत्ता और

अन्य (1998) 1 एससीसी 458 इस अदालत ने पाया कि माल दुलाई और हैंडलिंग शुल्क बिक्री मूल्य में शामिल किया जाएगा।

39. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली बनाम मारुति उद्योग लिमिटेड (2002) 3 एससीसी 547 इस अदालत ने निम्नानुसार देखा:

"प्रतिवादी द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य को उत्पाद शुल्क सहित संपूर्ण मूल्य माना जाना चाहिए क्योंकि यह प्रतिवादी है, जो आवश्यक रूप से निहितार्थ, बेची गई वस्तुओं पर सभी करों का भुगतान करने के दायित्व पर लिया गया है और क्रेता से प्राप्त कीमत के अतिरिक्त किसी भी राशि की वसूली की मांग नहीं की गई है। क्रेता स्क्रेप की कीमत के रूप में पहले से भुगतान की गई राशि से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था।"

40. ए.पी. राज्य बनाम ए.पी. पेपर मिल्स लिमिटेड (2005) 1 एससीसी 719 में विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी - मैसर्स द्वारा परिवहन शुल्क और एजेंट के कमीशन का भुगतान किया गया था। ए.पी. पेपर मिल्स लिमिटेड ने कच्चे माल की लागत के साथ एजेंट को धारा 2(एस) के तहत " "

सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 6-ए के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है। इस अदालत ने भरोसा किया हिंदुस्तान शुगर मिल्स

(सुप्रा) पर और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिवहन शुल्क और एजेंट का कमीशन धारा 2(एस) के तहत“ “

सामान्य बिक्री की धारा 6 (ए) के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है।
कर अधिनियम, 1957.

41. जब हम अंग्रेजी न्यायालयों और हमारे न्यायालयों के निर्णयों के अनुपात को लागू करते हैं, तो निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है कि डीलर द्वारा किए गए माल दुलाई और बीमा शुल्क की राशि बिक्री मूल्य का हिस्सा बनती है।

42. हम दोहरा सकते हैं कि इस मामले में, पार्टियों द्वारा और उनके बीच विशिष्ट अनुबंध किया गया था और अनुबंध के प्रासंगिक खंड के अनुसार, माल का स्वामित्व आपूर्तिकर्ता के पास तब तक रहेगा जब तक कि वे गंतव्य स्टेशन पर वितरित नहीं हो जाते।

43. अनुबंध की स्पष्ट धारा को देखते हुए कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं है। हमारे विचार में, ट्रिब्यूनल के फैसले की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से उचित था। किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये अपीलें किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण जुर्माने सहित खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार सिंहल, (आर.एच.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सीभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।